भवन निर्माण क्षेत्र की हरियाली बढ़ाने के लिए उन्नत सुधार की जरूरत

लखनऊ (सं.)। ऊर्जा संसाधन के अपव्यय पर अंकुश लगाने के लिए भवन निर्माण क्षेत्र की हरियाली बढ़ाने के लिए उन्नत सुधार की जरूरत है। संसाधन क्षमता के सही आकलन किए बिना अंधाधुंध प्रयोग से भवन निर्माण और शहरों में निवास को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यक और आवासीय भवन भारत के २८ प्रतिशत से अधिक ऊर्जा को गटक जाते हैं। 2030 में 70 प्रतिशत और भवनों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा सेन्टर फॉर साइंस एण्ड इन्वायरमेन्ट नई दिल्ली एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित हरित भवनों के लिए कार्यसूची पर अभिविन्यास कार्यशाला पर उपस्थित विशेषज्ञों ने कहे। दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के शहरों में हरित भवनों पर जमीनी कार्यवाही होने लगी है और कुछ प्रस्तावित है। दिल्ली मे 500वर्ग मीटर क्षेत्र वाले उद्योग, होटल, आस्पताल आदि और आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर प्रणाली अनिवार्य है। सोलर वाटर हीटर आदि की खरीद के लिए 6000 रुपये मूल्य की सब्सिडी की मंजूरी भी दी गई है। इस पर भी विचार हुआ कि भवनों के निर्माण इस प्रकार से हो कि दिन में सूर्य प्रकाश का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके और बिजली का उपयोग कम से कम करना पड़े। 2007 के बाद से सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों में तापदीप्त बल्बों को सीएफएल के साथ बदला गया है। ऊर्जा के औसत उपयोग को 25 से 40 प्रतिशत घटाने के लिए सरकारी भवनों में इसीबीसी द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। सौर ऊर्जा संयत्रों पर निर्भरता के लिए भी प्रेरित किया जाना बहुत ही आवश्यक बताया गया। उच्च विकासात्मक कार्यवाही के लिए मुद्दों में शहरों द्वारा प्रभावी संसाधन बचत सुनिश्चित किया जाए। घरों के लिए बढ़ते संकट के प्रति जोखिम कम करने के लिए काफी ऊर्जा बचाने की जरूरत है। अधिक कुशल प्रकाश व्यवस्था, एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन और वास्तुशिल्प डिजाइन के साथ 30 से 70 प्रतिशत ऊर्जा की बचत संभव है। ऊर्जा दक्षता ब्यौरो ने भी कहा है कि मौजूदा भवनों में भी 30 से 50 प्रतिशत ऊर्जा बचाने की क्षमता है। संगोष्ठी में अनुमिता रॉय चौधरी ने स्वागत भाषण दिया । प्रो. रितु गुलाटी, प्रमुख वास्तुविद दीपेन्द्र प्रसाद, वाशमी रंगा, एडीजी पीडब्लूडी आर के गोविल, इं एस पी श्रीवास्तव, निदीशक एआरआईएनईएम अनुपम मित्तल, डॉ. वेंकटेश दत्ता ने सम्बोधित किया।